(c) For augmenting the country's production of coconut oil Government has set up a Coconut Development Board for promoting coconut cultivation/development. Efforts are being made for improving the production by using modern techniques, i.e. Tissue Culture etc. Remunerative support prices are being announced annually. In order to give thrust for its development, coconut has been declared as an Oilseed. For improving the availability of indigenous, oilseeds, Government is continuing with oilseed production programme, oilseeds projects of N.D.D.B., setting up of Technology Mission on Oilseeds, intensification of research.

आयातित अखबारी कागज का आबंटन

1540. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज की आयात नीति के अधीन 56 प्रतिशत भारतीय और 35 प्रतिशत आयातित अखबारी कागज 200 मीट्रिक टन से अधिक की खपत वाले समाचारपत्रों को आवंटित किया जाता है;

(ख) क्या यह नियम सरकारी प्रकाशनों पर भी लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो 200 मीट्रिक टन से अधिक की वार्षिक खपत वाले "एम्पलायमेन्ट न्यूज" नामक साप्ताहिक को नियत आयातित अखबारी कागज से अधिक अखबारी कागज आवंटित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इससे विदेशी मुद्रा बचाने की सरकार की नीति पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देशी तथा आयातित अखबारी कागज का अनुपात देश में अखबारी कागज की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। वर्ष 1990-91 के दौरान यह अनुपात 65 : 35 था।

(ख) जी, हां।

(ग) "रोजगार समाचार" को विशेष मामले के तौर पर आयातित अखबारी कागज आवंटित किया जाता है।

(घ) सरकार द्वारा "रोजगार समाचार" का प्रकाशन देश के शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए किया जाता है। अतः इसका बिक्री मूल्य कम रखा गया है। इस समाचार पत्र के लिए केवल आयातित अखबारी कागज आबंटन भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयातित अखबारी कागज प्रायः देशी अखबारी कागज की तुलना में सस्ता होता है।

छोटे और मझोले समाचारपत्रों के संबंध में राम मोहन राव समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

1541. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मझोले समाचारपत्रों के संबंध में राम मोहन राव समिति की 27 दिसम्बर, 1990 को सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किये जा रहे छोटे समाचारपत्रों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की 12 सिफारिशों में से सरकार ने कुछ मामलों में थोड़ा सा संशोधन करने के बाद 11 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उम्मीद है कि

छोटे तथा मझौले समाचार पत्रों को उपलब्ध सुविधाओं तथा आधुनिकीकरण के लिए ऋणों की व्यवस्था होने से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

ईदे मिलादुन्नबी को छुट्टी

1542. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व प्रधान मंत्री ने 1990 में ईदे मिलादुन्नबी को राजपत्रित छुट्टी के रूप में मनाये जाने के बारे में घोषणा की थी और उस वर्ष उस दिन छुट्टी मनायी गई थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद इस छुट्टी को समाप्त कर दिया गया; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) गत वर्ष की तरह इस त्यौहार पर छुट्टी घोषित की जा रही है।

समाचारपत्रों की भाषावार संख्या

1543. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990 में प्रकाशित समाचार-पत्रों की भाषावार संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक समाचारपत्र की प्रसार संख्या कितनी-कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) वर्ष 1989 में प्रकाशित समाचार पत्रों की भाषावार अद्यतन उपलब्ध संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **देखिए** परिशिष्ट CLX, अनुबंध सं० 58)

(ख) प्रत्येक समाचार-पत्र की प्रसार संख्या देना संभव नहीं है क्योंकि सभी समाचार पत्र अपना वार्षिक विवरण भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय को नहीं भेजते।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने वाले इंजीनियर

1544. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च प्रभाव को देखते हुए कितने इंजीनियर इस सेवा में प्रवेश कर चुके हैं और कितने इंजीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठे; और

(ख) क्या सरकार देश के विकास में इंजीनियरों की तकनीकी दक्षता का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से उन्हें अन्य सेवाओं में जाने से रोकने के लिए उपाय करने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) सूचना निम्न प्रकार है:-

सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले इंजीनियरों की संख्या		भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त इंजीनियरों की संख्या
1988	1853	27
1989	1917	44
1990	2172	51

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में किसी भी विषय के स्नातक